

भारत की सुरक्षा के सन्दर्भ में नेपाल का स्रातेजिक महत्त्व

डॉ. एम.के. उनियाल

एसोसिएट प्रोफेसर, सैन्य विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

प्राचीन काल से भारत एवं नेपाल के सम्बन्धों का इतिहास इतना अधिक क्रमबद्ध, सुनिश्चित और घनिष्ठ रहा है कि इसके परिणामस्वरूप दोनों के जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यथा-सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समरूपता दृष्टिगोचर होती है। इस एकरूपता का विशेष कारण यह है कि अतीत काल में, जब नेपाली राजवंश की स्थापना नहीं हुई थी तब नेपाल के अधिकांश भू-भाग भारतीय साम्राज्यों के हिस्से थे अथवा दोनों भू-भागों में एक ही शासक थे।

नेपाल भारत का एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ सीमा पर कोई रोक-टोक नहीं है। इस सन्दर्भ में पुष्पेश पंत लिखते हैं कि "भारत और नेपाल इतने निकट और घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं कि कई बार लोग नेपाल को विदेश मानने को तैयार ही नहीं होते।" भारत-नेपाल के बीच लगभग 1800 किमी० लम्बी सीमा पर न कोई बाड़ है और न ही कोई अवरोध। सीमा को दर्शाने के लिए सिर्फ कंकरीट के स्तम्भ बने हुए हैं। दोनों देशों की सीमाएं एकदम से खुली हैं और दोनों देशों के नागरिकों के लिए आवागमन भी खुला हुआ है। नेपाल पूरब, पश्चिम और दक्षिण में भारत से तथा उत्तर में तिब्बत-चीन से जुड़ा हुआ है।

भारत की स्वंत्रता के पश्चात् भारत-नेपाल सम्बन्धों में एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में नेपाल ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। भारत-चीन संघर्ष में नेपाल पूर्णतः तटस्थ रहा और भारत भी यह नहीं चाहता था कि नेपाल इस संघर्ष में अपने को सम्मिलित करे। लेकिन नेपाल को चीन की विस्तारवादी नीति पर शंका अवश्य पैदा होने लगी और इस युद्ध के बाद नेपाल नरेश महेन्द्र ने भारत से सम्बन्ध सुधारने की स्थिति अनुभव की, इसलिए उन्होंने भारत-चीन युद्ध के दौरान कहा कि नेपाल ने कभी किसी अन्य देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही वह अन्य किसी देश का अपने मामले में हस्तक्षेप सहन कर सकता है। यह हम नेपालियों का जन्मजात गुण है कि एक मित्र के संकट के समय उससे सहानुभूति रखें क्योंकि नेपाली वीर होते हैं और विश्वासघात उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है। इस प्रकार भारत-नेपाल सम्बन्ध अधिकांशतः मधुर ही रहे हैं।

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत को अपने सामरिक हित को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देश के प्रति नीति में सुरक्षा के तत्व को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था। भारत की यह इच्छा थी कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, भूटान तथा सिक्किम की सरकारें, भारत विरोधी किसी शक्ति को इस क्षेत्र में न तो पनपने दें और न ही उससे निर्देशित हों।

इसलिए इन देशों को अपनी सुरक्षा परिधि में लाने के उद्देश्य से भूटान के साथ 8 अगस्त 1949 को, नेपाल के साथ 31 जुलाई 1950 तथा सिक्किम के साथ 5 दिसम्बर 1950 को सन्धियां की गयी। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति को और स्पष्ट करते हुए 22

मार्च, 1949 को इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली में नेहरू ने कहा था हमारी विदेश नीति केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है। परन्तु पड़ोसी देश के एक दूसरे के लिए विशेष हित होते हैं इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों से जो जमीन व समुद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, वर्मा, मलेशिया, इण्डोनेशिया व श्रीलंका के साथ सम्बन्धों को विशेष हितों के दृष्टिकोण से देखना होगा। नेपाल से स्थापित विशेष सम्बन्ध में भारत का मूल उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। यद्यपि सन्धि करने के पीछे यह भावना भी थी कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में प्राचीन सम्बन्ध, आर्थिक आत्मनिर्भरता व परस्पर राजनैतिक हित पूर्व की भाँति संचालित होते रहें। भारत का उद्देश्य यह भी था कि नेपाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी में सम्मिलित हो जाये। इससे उत्तर की ओर से चीन के बढ़ते खतरे व शीतयुद्ध के प्रभाव से भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था। क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा में निहित थी। नेपाल की सन्धि के द्वारा अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत करना आवश्यक था।

यद्यपि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं और इन साझा संस्कृतियों, रूढ़ियों एवं परम्पराओं को अलग किया जाना कठिन है फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि भारत के इतिहास में भारत और नेपाल में आपसी सम्बन्धों को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत की आजादी के समय नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था और महाराजा अपने समर्थ सबल-प्रधानमंत्री राणाओं के चंगुल में थे। राणाशाही से मुक्त होने की छटापटाहट नेपाल नरेश को भारत के करीब लायी। तब विशेष परिस्थितियों में भारत-नेपाल मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को संपन्न हुई।¹ इस ऐतिहासिक सन्धि का नेपाल 1960 तक अनुकरण करता रहा परन्तु 26 अप्रैल 1960 को नेपाल ने चीन के साथ मैत्री एवं रक्षा समझौता कर लिया, जो इस सन्धि के विरुद्ध था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भी नेपाल चीन से आर्थिक व सामरिक सहायता प्राप्त करता रहा। 1975 में नेपाल ने हठधर्मिता अपनाते हुए भारत से व्यापार व पारगमन पर अलग-अलग सन्धियों पर हस्ताक्षर किए जबकि पहले यह एक ही सन्धि में दोनों व्यवस्थाएं थी। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 1989 को दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पारगमन संधि समाप्त होने के बाद विवाद पैदा हो गया था।² 1988 के मध्य नेपाल ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइराला ने 1991 में भारत यात्रा के दौरान पुनः व्यापार तथा पारगमन सन्धि पर हस्ताक्षर करके तनाव कम किया। ज्ञातव्य है कि नेपाल ने सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया था।

8 अप्रैल 1990 को शताब्दियों से चले आ रहे असीमित राजतंत्र के स्थान पर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। महाराजा वीरेन्द्र ने जनता की इच्छा को स्वीकार करके निर्दलीय पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया और दलों पर आधारित

संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल के आर्थिक विकास में भारत की प्रतिबद्धता को 1992 के पश्चात अनेक कार्यक्रमों के द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया। फिर भी नेपाल की राजनीति में धीरे-धीरे चीन समर्थित कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता रहा जो कि नवम्बर 1994 के चुनावों में बढ़कर सत्ता तक पहुँच गया। कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत-नेपाल संबंधों पर नये सिरे से विचार होना प्रारंभ हो गया और यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत-नेपाल संबंध अब मधुर नहीं रहेंगे। नेपाल की प्रथम साम्यवादी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने 1995 में भारत की यात्रा की तथा भारत-नेपाल संबंधों के सभी क्षेत्रों की पुनर्समीक्षा का सुझाव दिया। इस यात्रा के द्वारा भारत तथा नेपाल के संबंधों के प्रति उत्पन्न कुछ ऐसी शंकाओं को दूर किया गया जो कि साम्यवादी सरकार के गठन के बाद उभरकर सामने आयी थी। भारत-नेपाल संबंधों में एक बहुत उत्तम स्तर तब आया जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 6 फरवरी 1996 के दिन महाकाली सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि द्वारा 2000 मेगावाट की सामर्थ्य वाले पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का 8 वर्षों में निर्माण करने तथा सराहा और टनकपुर जल भण्डारों का विकास करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जून 1997 में भारत के प्रधानमंत्री गुजराल ने नेपाल की यात्रा की तो मैत्री संबंधों की प्रक्रिया को और बल प्राप्त हुआ। मार्च 1998 में भारत में बनी बी.जे.पी. सरकार ने भारत-नेपाल संबंधों को विकसित करने की नीति अपनायी। अटल बिहारी वाजपेयी का पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध में यह मानना रहा है कि " मित्र बदले जा सकते हैं, परन्तु पड़ोसी नहीं। अतः पड़ोस में कौसी भी व्यवस्था हो उससे मधुर संबंध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अतः 1998 से 2004 तक के समय में भारत-नेपाल संबंध मित्रतापूर्ण एवं सहयोगी बने रहे हैं।

2008 में नेपाल की राजनीति में वर्चस्व कायम करने के बाद माओवादियों का भारत और हिन्दू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। नेपाल के ब्रह्मदेव नगर मण्डी सीमा से भारत में घुसपैठ करने वाले माओवादियों ने भारत मुर्दाबाद और "भारतीय सेनाओं नेपाल छोड़ो" जैसे नारे लगाये। भारत-नेपाल सीमा विभाजित करने के लिए लगाये गये खम्भों में अकिंत भारत शब्द को खरोंच कर मिटा दिया गया। जेहादी कठमुल्लों और माओवादियों का यह प्रयास रहा है कि नेपाल को भारत से दूर कर चीन के करीब कर दिया जाय और उसे भारत के खिलाफ इस्लामी आतंकवाद के केन्द्र के रूप में उपयोग लाया जाय।

1990 के दशक से नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संक्रमण की प्रक्रिया चल रही है। 2006 में लोकतांत्रिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप राजतंत्र को समाप्त कर नेपाल को एक पंथ निरपेक्ष तथा बहुसंस्कृति वाला देश घोषित किया गया था। जबकि इसके पहले नेपाल में राजशाही शासन तथा हिन्दू धर्म को नेपाल के राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1996 से 2006 तक के लोकतांत्रिक आन्दोलन में माओवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उन्हें युवाओं और जनता के कमजोर वर्गों का समर्थन भी प्राप्त हो गया था। नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति में माओवादियों का प्रवेश एक नई घटना थी, जिन्हें वैचारिक प्रेरणाला चीन से प्राप्त हो रही थी। परिणामस्वरूप इनका दृष्टिकोण भारत विरोधी रहा है। नेपाल का नया संविधान बनाने के लिए 2008 में

नेपाल की संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसमें माओवादियों को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुईं। माओवादियों ने 2008 में अन्य दलों के समर्थन से सरकार का गठन भी किया और माओवादी नेता के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने परम्परा को ताक पर रखते हुए अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत चीन से की। जबकि भारत-नेपाल विशेष संबंधों के रूप में इससे पहले एक अनौपचारिक परम्परा यह थी कि नेपाल के नये प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा में भारत ही आते थे। प्रचण्ड ने 1950 की भारत-नेपाल सन्धि को भारत की सम्प्रभुता के विरुद्ध बताते हुए उसे समाप्त करने की मांग की थी। भारत पर नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया गया। इसके साथ ही भारत-नेपाल में चलायी जा रही विकास योजनाओं को भारत विरोधी प्रदर्शनों को निशाना बनाया गया। जिसके कारण वर्तमान में भारत की सहायता से नेपाल के 75 जिलों में चल रही 420 विकास परियोजनाएं राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवरुद्ध पड़ी हैं।

भारत और नेपाल में सांस्कृतिक समानता होने के बावजूद भी समय-समय पर मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। चीन हमेशा से ही भारत-नेपाल मधुर संबंधों में बाधक रहा है। चीन ने नेपाल को अपने प्रभाव में लेने के कई प्रयास किए परन्तु भारत ने नेपाल को निरन्तर आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर वहां सड़कों के निर्माण और पानी बिजली के विकास में सहायता और सहयोग देकर मित्रतापूर्ण संबंध बनाये रखने के लिए चेष्टा की है। भारत-नेपाल के संबंधों के निर्धारण में चीन हमेशा से ही निर्णायक कारण रहा है। बिना चीन की भूमिका के भारत-नेपाल के संबंधों के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या वाला नेपाल दुनिया के अल्प विकसित देशों में से एक है। 141577 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला नेपाल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद दक्षिण एशिया में इसका भूराजनीतिक महत्व है, क्योंकि इसकी सीमाएं एशिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों चीन और भारत के साथ लगी हुई हैं। चीन के साथ इसकी लगभग 1236 किमी० तथा भारत के साथ 1751 किमी० सीमा रेखा है, इस तरह नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्त्रातजिक मूल्य रखता है। बीजिंग के अनुसार नेपाल चीन के आन्तरिक सुरक्षा घेरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी वैश्विक या क्षेत्रीय शक्ति इस सुरक्षा घेरे को तोड़े। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण से चीन के लिए नेपाल का स्त्रातजिक महत्व बढ़ गया है। बीजिंग के लिए नेपाल को तिब्बत मुद्दे पर उदासीन बनना तथा चीनी विद्रोही तिब्बती गतिविधियों के केन्द्र बनने से रोकना एवं शीतयुद्ध के बाद नेपाल में पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका की आर्थिक, राजनैतिक सहायता के रूप में उपस्थिति को रोकना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। अमेरिका के प्रभाव को कम करना तथा अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना भी नेपाल के लिए महत्वपूर्ण हो गया चीन के लिए नेपाल का महत्व सिर्फ इतना है कि चीन नेपाल का उपयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता है।

जब तक भारत-चीन सम्बन्ध सामान्य थे और तिब्बत भारत और चीन के बीच अन्तरस्थ राज्य के रूप में था तब तक नेपाल का स्त्रातजिक महत्व कम था, लेकिन जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उभरा और तिब्बत पर चीन का पूर्ण नियंत्रण हो गया, तब से नेपाल ने चीन का प्रयोग भारत के प्रभाव को

कम करने के लिए करना शुरू कर दिया तथा चीनी गणना में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया। 2005 में चीन और नेपाल के बीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धों की 50 वीं वर्षगांठ मनायी गयी। चीनी राष्ट्रपति हूजिंताओं ने 22 अप्रैल 2005 को आसियान सम्मेलन में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र से मुलाकात की और विचार विमर्श के पश्चात कहा कि नेपाल चीन का स्वभाविक मित्र और पड़ोसी है और हजारों वर्षों से दोनों देशों के बीच मित्रवत आदान-प्रदान होता रहा है तथा चीन नेपाल के बीच मित्रवत पड़ोसी व्यवहार चीन की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जुलाई 2005 में चीनी विदेशमंत्री जियलिंग ने नेपाली विदेशमंत्री रमेश नाथ पाण्डेय को सदर्श भेजा और कहा कि चीन-नेपाल सम्बन्ध उन देशों के लिए उदाहरण है जहां अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाते हुए 25 दिसम्बर 2005 में एक समझौता किया जिसमें दोनों देशों ने सांस्कृतिक, व्यापार, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का निर्णय लिया और नेपाल में चीनी निवेश तथा उद्यम लगाने पर भी सहमति प्रकट की। अप्रैल 2006 से शुरू जन आन्दोलन और अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ चीन नेपाल सम्बन्धों में आज तक लगातार वृद्धि देखने को मिली है।

भारत के लिए नेपाल का स्रातजिक महत्व 1990 के बाद उस समय और बढ़ गया, जब परत्परागत शत्रु पाकिस्तान ने नेपाल में अपनी आई०एस०आई० गतिविधियों के लिए केन्द्र स्थापित किया, ताकि वह भारत के खिलाफ कार्यवाही कर सके। 1999 में काठमाण्डू से भारतीय एयरलाइन्स के विमान आई०सी० का अपहरण एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन और पाकिस्तान ने नेपाल को लगातार सैनिक सहायता प्रदान की है यहां तक कि 2005 में इस्लामाबाद से रायल नेपाल आर्मी के सैनिकों को व्यापक ट्रेनिंग कैम्पू भी उपलब्ध कराये गये थे। इस प्रकार चीन के साथ-साथ पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बनाने के लिए नेपाल को महत्व देता रहा। यह तथ्य है कि भारत के लिए नेपाल तथा नेपाल के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित नेपाल जैसे लघु राज्य को भारत जैसे बड़े देश को इसलिए गंभीरता से लेना पड़ा है, क्योंकि यह अपने भू-स्रातजिक अवस्थिति के कारण चीन तथा मध्य भारत के मध्य बफर राज्य का कार्य करता है। चीन द्वारा नियंत्रित और संचालित नेपाल या भारत द्वारा नियंत्रित एवं संचालित नेपाल एक-दूसरे के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ नेपाल को भारत की आवश्यकता है क्योंकि नेपाल जो कि पूरी तरह थल सीमा से आबद्ध है, उसे अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत नेपाल सम्बन्धों का मधुर होना अनिवार्य आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति की सक्रियता का संकेत देने के लिए भारत के नये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2014 को नेपाल की सरकारी यात्रा सम्पन्न की है। यह यात्रा भारत व नेपाल के सम्बन्धों को पटरी पर लाने में सहायक होगी। यात्रा के अन्त में 4 अगस्त 2014 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं-

1 दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परस्पर सम्बन्धों को बढ़ाने तथा व्यापार, पारगमन, जल विद्युत भौतिक सम्पर्कता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नये अवसरों को खोजने की आवश्यकता

पर बल दिया।

- 2 दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था प्रकट की और शान्ति और विकास के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
- 3 बदली हुई परिस्थितियों के बहुआयामी व गहरे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के विदेश सचिवों को 1950 की मैत्री सन्धि के एक नये मसौदे को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- 4 भारत द्वारा नेपाल को एक बिलियन डालर के सस्ते ऋण की घोषणा की गयी है। जिसका प्रयोग नेपाल द्वारा आधारभूत ढाँचे के विकास ऊर्जा योजनाओं को लागू करने में किया जायेगा।
- 5 संयुक्त वक्तव्य में भारत ने नेपाल की कई विकास परियोजनाओं में वित्तीय व तकनीकी सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है।
- 6 दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल सीमा के विवादास्पद बिन्दुओं के स्थाई समाधान हेतु सहमति व्यक्त की है।
- 7 दोनों नेताओं ने सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है।
- 8 दो नये समझौतों को अन्तिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की गई है, इनमें एक समझौता प्रोजेक्ट डेवलपमेण्ट के बारे में है तथा दूसरा समझौता ऊर्जा के व्यापार से सम्बन्धित है।

नेपाल ने इस यात्रा के दौरान अपने यहाँ हो रहे व्यापार घाटे का मामला भी उठाया। भारत का मत है कि नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाये जिससे भारत-नेपाल से जल विद्युत का आयात कर सके और नेपाल के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। भारत-नेपाल में स्थिरता, विकास तथा लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक है। एक तरफ वर्तमान में नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन का प्रभाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ नेपाल की पहली संविधान सभा नेपाल के नये संविधान का निर्माण नहीं कर सकी है और इसे भंग कर नवम्बर 2013 में संविधान सभा के पुनः चुनाव कराये गये, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकारों में कई बार बदलाव हुआ है। और आज तक नये संविधान का निर्माण अधर में लटका हुआ है। नेपाल की यह राजनीतिक अस्थिरता भारत व नेपाल के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

उक्त विश्लेषण एवं अध्ययन के आधार पर भारत नेपाल सम्बन्धों के दुलमुल रवैये को देखते हुए यदि दोनों देशों के नीति निर्माता निम्न सुझावों को अपनी नीतियों में शामिल करें तो निश्चित ही इनके पारस्परिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आयेगी और उसे एक नई दिशा मिल सकेगी। ये सुझाव इस प्रकार हैं-

- 1 दोनों देशों को एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अखण्डता का सम्मान करना चाहिए, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा एक दूसरे की भूमि से एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए।
- 2 भारत को नेपाल के सामरिक महत्व को देखते हुए नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए हर तरफ की सहायता में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।
- 3 आई. एस. आई. का प्रभाव क्षेत्र जो नेपाल में दिन-प्रतिदिन

बढ़ रहा है पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों को संयुक्त कार्य बल गठित करना चाहिए तथा इसके विरुद्ध स्थानीय लोगों की सहायता लेते हुए लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।

- 4 चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ विवादित मुद्दों को हल करने का प्रयास तेज करना चाहिए।
- 5 दोनों राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना चाहिए।
- 6 शरणार्थियों एवं गैरकानूनी तौर पर रह रहे नागरिकों की समस्या पर दोनों राष्ट्रों को परस्पर विचार विमर्श के द्वारा

एक निर्णायक व सुदृढ़ प्रयास करना चाहिए।

- 7 दोनों देशों की मीडिया तंत्र की भूमिका सार्थक व उत्तरदायित्वपूर्ण होनी चाहिए।
- 8 दोनों राष्ट्रों को ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए जिनसे सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों में खटास आने की आशंका हो।

सन्दर्भ सूची

- 1 पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, भारतीय विदेश नीति, नये आयाम, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000, पृ0-167
- 2 सिंह, लल्लनजी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2017, पृ0-676
- 3 पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, पूर्वोक्त, पृ0-170